

गामिनी कृष्णय्या और अन्य

बनाम

कुर्जा सेशाचलम और अन्य

31 अगस्त, 1964

(रघुबर दयाल, जे. आर. मुधोलकर और एस. एम. सिकरी जे.)

मद्रास कृषक राहत अधिनियम (1938 का 4)। 9 (1) और 13 1
अक्टूबर 1932 के बाद लेकिन अधिनियम के प्रारंभ से पहले उपगत ऋण
अधिनियम के प्रारंभ के बाद नवीनीकरण-लागू प्रावधान।

अपीलार्थियों (लेनदारों) के परिवार और उत्तरदाताओं (देनदारों) के
परिवार के बीच लेन-देन 1934 में शुरू हुआ। सितंबर 1938 में, मार्च 1938
में मद्रास कृषि राहत अधिनियम (1938 का 4) के लागू होने के बाद,
देनदारों (जो कृषक हैं) द्वारा लेनदारों के पक्ष में एक वचन पत्र निष्पादित
किया गया था। देनदार उस राशि पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज
देने के लिए भी सहमत हुए। 1951 में लेनदारों को देय राशि पर पहुंचने में,
देनदारों ने तर्क दिया कि ऋण को एस के तहत कम किया जाना चाहिए।
9 (1) जबकि लेनदारों ने इस आधार पर तर्क दिया कि यह अधिनियम
के प्रारंभ के बाद उपगत एक ऋण था, कि एकमात्र राहत जिसके लिए
देनदार हकदार थे, एस के तहत ब्याज की गणना थी। 13 अधिनियम से।

पकड़ना: यद्यपि लेन-देन अधिनियम की शुरुआत के बाद किया गया था, क्योंकि मूल ऋण अधिनियम के लागू होने से पहले उत्पन्न हुआ था, लेकिन 1 अक्टूबर, 1932 के बाद। 9 (1) अधिनियम लागू होगा। [210 डी]

एस के तहत। 7 अधिनियम के प्रारंभ में एक कृषक द्वारा देय प्रत्येक ऋण को कम किया जाएगा और कम की गई राशि से अधिक कुछ भी वसूली योग्य नहीं होगा और यह प्रभावी रूप से शेष दायित्व के निर्वहन के रूप में काम करेगा। इसलिए, जहां एक कृषक से ऋण की वसूली के लिए एक मुकदमा दायर किया जाता है, वहां न्यायालय को ऋण को कम करना होगा जैसा कि एस में प्रदान किया गया है। 8 यदि डेस्ट 1 अक्टूबर, 1932 से पहले किया गया था। यदि उस तारीख के बाद ऋण लिया गया था, तो न्यायालय को एस के प्रावधानों को लागू करना होगा। 9. ऐसे मामले में, अधिनियम के प्रारंभ के बाद किया गया ऋण समाप्त नहीं होगा।

1 अक्टूबर, 1932 के बाद उपगत ऋण होगा, जब यह अधिनियम के प्रारंभ से पहले उत्पन्न दायित्व के नवीकरण में लेन-देन है। जिस बारे में भविष्य का ब्याज, अधिनियम के प्रारंभ से पहले के लेन-देन एस. एस. द्वारा कवर किए जाते हैं। 8 और 9, एस द्वारा शासित हैं। 12 , और अधिनियम के प्रारंभ के बाद लेनदेन, एस द्वारा। 13. एस को अधिनियमित करने में विधानमंडल का उद्देश्य। 13 अधिनियम की शुरुआत के बाद पहली

बार किए गए ऋणों पर केवल किसानों द्वारा देय ब्याज की अधिकतम दर का प्रावधान करना है। [200 एफ-जी; 201 सी-ई; 204 सी-एफ]।

मामला कानून की समीक्षा की गई।

नागभूषणम बनाम। सीतारामैया, आई. एल. आर. [1961] 1 ए. पी. 485, अनुमोदन एड।तिरुवेंगदथा अय्यंगार बनाम। सन्नप्पर सरवाई, आई. एल. आर. (1942) पागल। 57 , खारिज कर दिया। सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 618 1961 .

1ओ. [1965] 1 एस सी आर। 196

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए दिनांकित निर्णय और डिक्री से विशेष अनुमति द्वारा अपील 1956 की दूसरी अपील संख्या 653 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का 23 दिसंबर, 1960 का आदेश।

के. भीमासांकरम, सी. एम. राव और के. आर. शर्मा अपीलार्थी।

उत्तरदाताओं के लिए ए. वी. वी. नायर और पी. राम रेड्डी, संख्या। 2 बी. और 4. न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था: जे. मुधोलकर इस मामले में निर्णय के लिए जो प्रश्न आता है उच्च न्यायालय के फैसले से विशेष अनुमति द्वारा अपील आंध्र प्रदेश एक ऋणी है जिसने

मद्रास कृषकों के लागू होने के बाद एक वचन-सी सोरी नोट को निष्पादित किया है।

राहत अधिनियम, 1938 (1938 का मद्रास अधिनियम 4) (इसके बाद संदर्भित)

अधिनियम के रूप में) अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए ऋण के नवीनीकरण में एस के लाभ का दावा करने का हकदार है। 9 में से

अधिनियम। निचली अदालत ने देनदार के तर्क को बरकरार रखा लेकिन अपील करने वाले अधीनस्थ न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया और अपीलकर्ताओं के डी सूट को पूरा करने का फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्याख्या रखी गई अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर गलत था, अपील की अनुमति दी और निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री को बहाल किया। इसकी सराहना करने के लिए कुछ तथ्यों को बताना होगा पक्षों की दलीलें। वादी जो अपीलार्थी हैं हमसे पहले और चौथे प्रतिवादी ने एक हिंदू संयुक्त का गठन किया परिवार जिसमें से पहला वादी वर्ष तक प्रबंधक था 1944 जब चौथा प्रतिवादी बाकी से अलग हो गया और शेष सदस्य संयुक्त बने रहे। सितंबर को 14,1938 संयुक्त परिवार एफ के प्रबंधक के रूप में पहला प्रतिवादी स्वयं से मिलकर, दूसरा और तीसरा प्रतिवादी निष्पादन प्रबंधक

के रूप में पहले वादी के पक्ष में एक वचन पत्र वादी और चौथे से मिलकर बना संयुक्त परिवार रुपये की राशि के लिए प्रतिवादी। 9,620-2-9 और ब्याज देने के लिए सहमत हो गए। 9 और 3/8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से। यह राशि मिली थी। वादी के परिवार और जी के पैर पर प्रतिवादी संख्या 4 के कारण उस परिवार और प्रतिवादियों के परिवार के बीच लेनदेन 1 से 3 जिसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। 1949 के मूल सूट संख्या 84 में चौथे डिफेन द्वारा लाया गया पारिवारिक संपत्ति के विभाजन के लिए वादी के खिलाफ मुकदमा पहले प्रतिवादी ने रुपये की राशि जमा की। 13,576-0-OB17 मार्च को, 1951 यह आरोप लगाते हुए कि यह राशि परिवार को देय थी प्रतिवादियों के परिवार से वादी और प्रतिवादी संख्या 4 14 सितंबर, 1938 के वचन पत्र के आधार पर 3 तक। मैं। यह अच्छा है।

1 कृष्णय्या बनाम। सेशाचलम (जे. मुधोलकर) 197

इस राशि पर पहुंचने पर प्रतिवादियों ने 1 से 3 को ध्यान में रखा अधिनियम के प्रावधानों और एस द्वारा अनुज्ञा के रूप में ब्याज को कम किया गया। 9 (1) अधिनियम से। वादी ने शुद्धता पर विवाद किया गणना जिसके बाद प्रतिवादियों 1 से 3 ने वापस ले लिया उनका आवेदन लेकिन फिर भी वादी ने वापस ले लिया द. अंततः राशि। इसके बाद वादियों ने मुकदमा दायर किया जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है

जिसमें उन्होंने दावा किया था रु. 3,858-13-3 और की गई गणनाओं के आधार पर लागत उनके द्वारा और शिकायत के साथ ज्ञापन में निर्धारित किया गया। प्रतिवादी 1 से 3 ने वादी के दावे का खंडन किया और कहा कि विभाजन वाद में उनके द्वारा जमा की गई राशि सितंबर के वचन पत्र के आधार पर ये प्रतिवादी तारीख 14,1938.ट्रायल कोर्ट, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ने काफी हद तक बरकरार रखा प्रतिवादियों का 1 से 3 तक का विवाद और रुपये के लिए एक डिक्री पारित की। 92-2-2 वादी और चौथे प्रतिवादी के पक्ष में और शेष राशि के संबंध में मुकदमा खारिज कर दिया। अपीलीय अदालत द्वारा दरकिनार किए गए इस आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा बहाल कर दिया गया है। वादियों की ओर से जो हमारे सामने अपीलकर्ता हैं श्री भीमासांकरम द्वारा यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया है कि अधिनियम का प्रासंगिक प्रावधान जिसके संदर्भ में वाद में वचन पत्र द्वारा प्रमाणित ऋण के समान ऋण को कम किया जा सकता है। 13 और एस नहीं। 9 जैसा कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है। एस का प्रासंगिक भाग। 13 इस प्रकार पढ़ता है: " ऋण की वसूली के लिए किसी भी कार्यवाही में, न्यायालय किसी भी ऋण पर देय सभी ब्याज को कम कर देगा। इसकी शुरुआत के बाद एक कृषक द्वारा अधिनियम, ताकि प्रति 6t पर गणना की गई राशि से अधिक न हो प्रतिशत प्रति वर्ष सरल ब्याज, अर्थात्, एक पाई प्रति रुपया प्रति माह साधारण ब्याज, या एक एना प्रति रुपया प्रति वर्ष सरल ब्याज: बशर्ते कि राज्य सरकार,

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना। किसी को भी बदलें और ठीक करें समय-समय पर ब्याज की अन्य दर "।विद्वान वकील के अनुसार वचन पत्र के निष्पादन ने स्वयं एक ऋण को अस्तित्व में लाया और चूंकि 14 सितंबर, 1938 को सर्वनाम को निष्पादित किया गया था, इसलिए इसके द्वारा प्रमाणित ऋण को शुरू होने के बाद किया गया माना जाना चाहिए। अधिनियम और इसके परिणामस्वरूप एस। 13 केवल ब्याज की गणना के उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की सीखी गई

[1965] एस सी आर। 198

वकील ने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि मूल ऋण ए उत्तरदाताओं में से 1 से 3 की शुरुआत वर्ष 1934 में हुई थी। लेकिन उनके अनुसार उनके खिलाफ जो दायित्व लागू करने की मांग की गई थी, वह वचन पत्र से उत्पन्न हुआ था। दिनांक 14 सितंबर, 1938 और इसलिए, ऋण को वाद में वचन पत्र के निष्पादन की तारीख को किया गया माना जाना चाहिए। मद्रास और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के कुछ फैसलों पर भरोसा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम किसानों द्वारा किए गए ऋण को तीन वर्गों में विभाजित करता है: (1) 1 अक्टूबर, 1932 से पहले किए गए खर्च; (2) 1 अक्टूबर, 1932 को या उसके बाद किए गए खर्च लेकिन उससे पहले किए गए खर्च।

अधिनियम का लागू होना और (3) अधिनियम के लागू होने के बाद किए गए खर्च। धारा 8 ऋण की पहली श्रेणी पर लागू होती है: . . . 9 ऋणों और ऋणों की दूसरी श्रेणी में। 13 ऋणों की तीसरी श्रेणी में। चूंकि, तर्क के पक्ष में, इन सभी प्रावधानों में उस तारीख का संदर्भ है जिस पर ऋण लिया जाता है और चूंकि ऋण केवल एक बार लिया जा सकता है, इसलिए यह होगा कि इन प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए जिस तारीख को ऋण के संदर्भ में अंतिम लेन-देन हुआ था, उस तारीख को ऋण लिया जा सकता है। उनके अनुसार इसका परिणाम यह होगा कि एस के प्रावधान। 8 उप-परंतुक के प्रावधानों के अधीन रहते हुए केवल तभी लागू होगा जब अंतिम लेन-देन 1 अक्टूबर, 1932 से पहले किया गया था। एस. (1) एस. 9 ; एस के प्रावधान। 9 केवल उस मामले में लागू होगा जहां अंतिम लेनदेन किया गया था अधिनियम और एस के प्रावधान। 13 शुरू होने के बाद जहां अंतिम लेनदेन किया गया था, वहां यह लागू होगा। अधिनियम से। के प्रावधानों को पूरी तरह से निर्धारित करना वांछनीय है दोनों एसएस। 8 और 9. वे इस प्रकार हैं: " 1 अक्टूबर, 1932 से पहले किए गए ऋणों को नीचे उल्लिखित तरीके से कम किया जाएगा। अर्थात्:

(1) 1 अक्टूबर, 1937 को किसी भी कृषक के पक्ष में बकाया सभी ब्याज चाहे वह कानून, प्रथा या अनुबंध के तहत या अदालत की डिक्री के तहत देय हो और क्या ऋण या अन्य दायित्व डिक्री में परिपक्व हो गया है या नहीं, उसे निर्वहन माना जाएगा और केवल मूलधन या उसका ऐसा

हिस्सा जो हो सके राशि बकाया राशि को उस तारीख को कृषक द्वारा चुकाया जाने वाला माना जाएगा।

(2) जहां एक कृषक ने किसी लेनदार को मूलधन की दोगुनी राशि का भुगतान किया है, चाहे वह ऋषभ वी. सेशाचलम (जे. मुधोलकर) हों। मूलधन या ब्याज या दोनों के रूप में, ऐसा ऋण मूलधन सहित, पूरी तरह से माना जाएगा छुट्टी दे दी।

(3) जहां मूलधन के रूप में चुकाई गई राशि या ब्याज या दोनों दोगुनी राशि से कम हो जाते हैं। मूलधन, ऐसी राशि जो केवल पूरी होगी यह कमी, या मूल राशि या ऐसा हिस्सा मूल राशि जो बकाया है जो कभी छोटा होगा, उसे चुकाया जाएगा।

(4) धारा 22 से 25 के प्रावधानों के अधीन उप-धारा (1), (2) और (3) में कुछ भी नहीं है। ऐसा माना जाएगा कि लेनदार को धनवापसी की आवश्यकता है कोई राशि जो उसे दी गई हो, या बढ़ाने के लिए किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए देनदार का दायित्व उस राशि का जिसका भुगतान किया जाना था यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता।

व्याख्या 1: पुनर्भुगतान राशि निर्धारित करने में इस धारा के तहत एक देनदार द्वारा सक्षम, प्रत्येक भुगतान उसके द्वारा किए गए ऋण को मूलधन की ओर डेबिट किया जाएगा, जब तक कि उसने लिखित रूप

में स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि भुगतान ब्याज में कमी के रूप में होगा।
व्याख्या II: जहाँ मूलधन उधार लिया गया था इसे नकद में भुगतान करने
के लिए एक समझौते के साथ, ऋणी, ऐसे समझौते के बावजूद, कटौती के
बाद ऋण को नकद में चुकाने का हकदार हो उसके द्वारा किए गए सभी
भुगतानों का मूल्य, ऐसे समझौते में निर्धारित दर, यदि कोई हो, पर, या
यदि ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो बाजार दर पर प्रत्येक भुगतान के समय
प्रचलित।

व्याख्या III: जहाँ ऋण का नवीनीकरण किया गया हो। या इससे
पहले निष्पादित एक नए दस्तावेज़ में शामिल या इस अधिनियम के
प्रारंभ के बाद, चाहे एक ही या एक अलग देनदार और क्या पक्ष में है
एक ही या एक अलग लेनदार का मूलधन मूल रूप से इस तरह की
राशियों के साथ अग्रिम, यदि जैसा कि बाद में आगे बढ़ाया गया है अकेले
प्रधान को ही प्रधान माना जाएगा। इस धारा के तहत देय राशि।

धारा 9: 1 अक्टूबर को या उसके बाद किए गए ऋण
1932 को पुरुषों के तरीके से कम किया जाएगा। जिसका उल्लेख नीचे
किया गया है: (1) ब्याज की गणना कॉम तक की जाएगी।

इस अधिनियम को [1965] एस. सी. आर. पर लागू दर पर
लागू करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 200

न्यायालय के कानून, सीमा शुल्क, अनुबंध या डिक्री के तहत ऋण जिसके तहत यह उत्पन्न होता है या पांच प्रतिशत प्रति ऋण पर।

वार्षिक सरल ब्याज, जो भी कम हो और ब्याज के लिए भुगतान की गई सभी राशियों के लिए क्रेडिट दिया जाएगा, और केवल ऐसी राशि के लिए जो बकाया पाई जाती है, यदि कोई हो।

इस प्रकार जमा किए गए ब्याज को देय माना जाएगा बी मूल राशि या ऐसे हिस्से के साथ जैसा कि देय है: बशर्ते कि ऋण का कोई भी हिस्सा जो पाया जाता है पूर्व ऋण का नवीकरण होना (चाहे समान या अलग ऋणी और क्या पक्ष में है उसी या किसी अन्य लेनदार का) सी को उस तारीख को अनुबंधित ऋण माना जाएगा जिस दिन ऐसा पूर्व ऋण किया गया था, और यदि ऐसा ऋण था 1 अक्टूबर 1932 से पहले अनुबंधित किया जाएगा एस के प्रावधानों के तहत निपटा गया। 8. (2) धारा 22 से 25, डी के प्रावधानों के अधीन यहाँ कुछ भी नहीं। यह माना जाएगा कि लेनदार को भुगतान की गई किसी भी राशि को वापस करने की आवश्यकता है उसे या ऋणी के दायित्व को बढ़ाने के लिए उस राशि से अधिक राशि का भुगतान करें जो उसके द्वारा देय होती यदि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता।" हम इन प्रावधानों और अन्य प्रासंगिक बातों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे। निर्णयों को संदर्भित करने से पहले अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान प्रत्येक पक्ष की ओर से

किस पर निर्भरता रखी गई है अपील के लिए। अधिनियम का दूसरा अध्याय "ऋणों को कम करने और एफ" से संबंधित है। भविष्य की ब्याज दर "। धारा 7 सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। एत प्रावधान क्योंकि यह यहाँ है कि विधायिका है एक अधिदेश दिया गया है कि एक कृषक द्वारा देय प्रत्येक ऋण अधिनियम के प्रारंभ को कम किया जाएगा और वह इस प्रकार कम की गई राशि से अधिक कुछ भी वसूल नहीं किया जाएगा। ऐसे देनदार से सक्षम। वह खंड इस प्रकार है: " किसी भी कानून, प्रथा, अनुबंध या डिक्री के बावजूद

इसके विपरीत, इस अधिनियम के प्रारंभ पर एक कृषि कृषक द्वारा देय सभी ऋण - के प्रावधानों के अनुसार कम किया गया यह अध्याय। इस प्रकार कम की गई राशि से अधिक कोई राशि नहीं होगी। उससे या किसी भूमि या ब्याज से वसूली योग्य हो

कृष्ण बनाम सेशाचलम (जे. मुधोलकर) 201

जहां तक ऐसी डिक्री इस अध्याय के तहत कम की गई राशि से अधिक राशि के लिए है, न ही उसकी संपत्ति कुर्क करने और बेचने या उसके खिलाफ किसी भी तरह से कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगी। हमें इस धारा के प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा। धारा 8,9 और 13 सहित अध्याय 2 के अन्य प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए। जहाँ वसूली के

लिए न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर किया जाता है। एक कृषक से ऋण के मामले में न्यायालय ने उस दस्तावेज को ध्यान में रखते हुए, जिसके आधार पर लेनदार ने एक मुकदमा दायर किया था, पाया कि उस दस्तावेज को 1 अक्टूबर, 1932 से पहले निष्पादित किया गया था, उसे ऋण को कम करने के लिए आगे बढ़ना होगा। धारा 8 में उल्लेख किया गया है। यदि यह पता चलता है कि ऋण बाद में वहन किया गया था 1 अक्टूबर, 1932 को इसे एस के प्रावधानों को लागू करना होगा। 9 में से अधिनियम। ये दो व्यापक श्रेणियाँ हैं जिनमें ऋण हैं। अधिनियम के तहत विभाजित किया गया। लेकिन, श्री भीमासांकरम ने तर्क दिया कि एक तीसरी श्रेणी भी है और यही वह जगह है जहाँ ऋण लिया जाता है। अधिनियम के प्रारंभ के बाद। एक अर्थ में वह सही है क्योंकि एस। 13 के स्केलिंग डाउन के लिए भी प्रदान करता है शुरू होने के बाद किए गए ऋण पर देय ब्याज एक्ट करें। लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि इसके बाद लिया गया ऋण अधिनियम का प्रारंभ एक ऋण होना बंद नहीं होगा 1 अक्टूबर, 1932 के बाद। यह एक आम जगह है कि हर कानून के प्रावधान को पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए और जहाँ भी संभव है कि अदालत को उस निर्माण को एक पर नहीं रखना चाहिए प्रावधान जो इसे अनावश्यक या अतिव्यापी बना देता है एक अन्य प्रावधान या इसकी अवहेलना में इसके आवेदन को सीमित करना सामान्य प्रयोज्यता जब तक कि, निश्चित रूप से, यह एकमात्र अर्थ नहीं है जिसे उचित रूप से

उस पर रखा जा सकता है। अगर श्री भीम शंकरम के तर्क को स्वीकार किया जाता है हमें सीमित करना होगा एस का अनुप्रयोग। 9 केवल अक्टूबर के बाद किए गए ऐसे ऋणों के लिए बीआर 1,1932 जैसा कि शुरू होने से पहले किया गया था एक्ट करें। खंड की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके प्रावधानों को सीमित करना उचित होगा। न ही फिर से कोई है धारा 13 में ऐसी बात है जो एस के अनुप्रयोग को रोक देगी। 9 प्रारंभ के बाद किए गए ऋण के किसी भी मामले में अधिनियम से। हो सकता है कि कंपनी के बाद कोई ऋण लिया गया हो। अधिनियम का उल्लेख इस अर्थ में कि अंतिम लेन-देन ऋण के संबंध में प्रवेश किया जा सकता है, इसके बाद अधिनियम का प्रारंभ। लेकिन वह लेन-देन हो सकता है शुरू होने से पहले उत्पन्न दायित्व का नवीनीकरण अधिनियम से। जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ 202 को बाहर करना मुश्किल है।

[1965] 1 एस सी आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस की प्रयोज्यता। 9 अधिनियम से। इस बारे में कि 1 अक्टूबर, 1932 के बाद किए गए ऋण के संबंध में ब्याज की गणना कैसे की जानी है, न्यायालय उप-धाराओं के प्रावधानों की अनदेखी नहीं कर सकता है। (1) एस. 9. हालाँकि, यह तर्क दिया गया था कि जहां अंतिम लेन-देन अधिनियम के प्रारंभ के बाद हुआ था, अदालत के पास इसके पीछे जाने

और यह पता लगाने की कोई शक्ति नहीं है कि लेन-देन की अंतिम तिथि तक लेनदार द्वारा क्या ब्याज लिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां पक्षों के बीच खातों का निपटान किया गया है और निपटान किए गए खातों के आधार पर उनके बीच एक नया लेनदेन किया जाता है, आम तौर पर, अदालत को अनुबंध अधिनियम के कुछ प्रावधानों में परिकल्पित परिस्थितियों को छोड़कर आगे की जांच करने की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन फिर वहाँ हैं ब्याज ऋण अधिनियम और विचाराधीन अधिनियम जैसे विशेष प्रावधान जो अदालतों को अपेक्षित शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ ऐसी शक्ति विशेष रूप से अध्याय II के तहत न्यायालयों को दी गई है। अब, उप-ओं के लिए प्रावधान। (1) एस. 9 स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऋण का कोई भी हिस्सा जो पूर्व ऋण का नवीनीकरण पाया जाता है

जिस तारीख को ऐसा पूर्व ऋण वहन किया गया था, उस तारीख को अनुबंधित ऋण माना जाएगा। इसलिए, हालांकि एक वचन पत्र को अधिनियम के प्रारंभ के बाद निष्पादित किया गया होगा यदि यह वास्तव में पूर्व ऋण के नवीनीकरण में था, तो इसे इस तरह माना जाना चाहिए जैसे कि यह पूर्व ऋण किए जाने के समय किया गया ऋण था। यह परंतुक का सही अर्थ प्रतीत होता है, हालांकि श्री भीमासांकरम के अनुसार यह मूल रूप से 1 अक्टूबर, 1932 से पहले किए गए ऋण से संबंधित है। अपने तर्क के समर्थन में श्री भीमशंकरम परंतुक के समापन भागों पर भरोसा करते हैं जो इस प्रकार हैं: और अगर ऐसा है ऋण 1 अक्टूबर 1932

से पहले अनुबंधित किया गया था, धारा 8 के प्रावधानों के तहत निपटा जाएगा। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि 'और' संयोजन का उपयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि परंतुक 1 अक्टूबर 1932 से पहले अनुबंधित ऋणों पर उतना ही लागू होता है जितना कि 1 अक्टूबर 1932 के बाद अनुबंधित ऋणों पर लागू होता है। हो सकता है कि वे अधिनियम के प्रारंभ के बाद किए गए हों। यदि वास्तव में विधानमंडल का इरादा श्री भीमसेन करम द्वारा सुझाए गए तरीके से परंतुक को लागू करने को सीमित करना था, तो विधानमंडल के लिए यह कहना आसान होता कि "बशर्ते कि कोई भी ऋण या ऋण का कोई भी हिस्सा जो ऋण के रूप में पाया जाता है।

1 अक्टूबर, 1932 से पहले अनुबंधित ऋण का नवीनीकरण "परंतुक के उस भाग में व्यक्त" पूर्व ऋण "का उपयोग करने के बजाय और फिर समापन अंश में कहें कि" यदि ऐसा ऋण 1 अक्टूबर, 1932 से पहले अनुबंधित किया गया है "। फिर श्री भीमासान करम ने तर्क दिया कि परंतुक उप-ओं के लिए है। (1) एस. 9 और इसलिए, के बाद नवीनीकृत ऋण को गले लगाने के लिए विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए अधिनियम का प्रारंभ। इस तर्क को स्वीकार करने के लिए कृष्णय्या वी. सेशाचलम (जे. मुधोलकर) होंगे। 203 इस जिज्ञासु स्थिति को बढ़ाते हुए कि अधिनियम के लागू होने के बाद नवीनीकृत ऋण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 अक्टूबर, 1932 को उपगत ऋण नहीं होगा। श्री भीमासांकरम द्वारा प्रस्तुत एक अन्य तर्क यह है कि जब तक कोई कानून

इस आशय का प्रावधान नहीं करता है कि किसी ऋण को कुछ परिस्थितियों में निर्वहन माना जाएगा, तब भी इसका भुगतान करने का दायित्व देनदार पर बना रहेगा और केवल ब्याज को कम करने के लिए प्रावधान करना पर्याप्त नहीं है। इस कौन में नेक्शन वह उप-ओं में प्रावधान को संदर्भित करता है। (1) एस. 8. के तहत कि 1 अक्टूबर, 1937 को बकाया प्रावधान ब्याज एक कृषक के किसी भी लेनदार को छुट्टी दे दी गई मानी जाएगी। और केवल मूलधन या उसका ऐसा भाग जो निकल सके। कृषि द्वारा देय राशि को देय राशि माना जाएगा। उस तारीख को संस्कृतिवादी। एस की उप-धारा (2)। 8 आगे प्रदान करता है कि जहाँ एक कृषक ने लेनदार को दोगुना भुगतान किया है राशि चाहे मूलधन, ब्याज या दोनों के रूप में, संपूर्ण ऋण को पूरी तरह से चुकाया हुआ माना जाएगा। यह सच है कि उप-एस। (1) एस. 9 जो किए गए ऋणों को कम करने का प्रावधान करता है 1 अक्टूबर, 1932 को या उसके बाद समान भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भाषा में कोई अंतर नहीं होगा सब-एस पढ़ने के कारण परिणाम में अंतर। (1) एस. 9 साथ में एस के प्रावधानों के साथ। 7 यह बहुत स्पष्ट है कि क्या डिटर अदालत से क्या प्राप्त करने का हकदार होगा और अदालत को केवल उस हद तक ब्याज देना होगा उप-ओं द्वारा अनुमेय। (1) एस. 9 और यह प्रभावी रूप से काम करेगा ब्याज के लिए शेष दायित्व के निर्वहन के रूप में पक्षों के

बीच अनुबंध। विद्वान वकील ने आगे कहा कि उपबंधों के प्रावधानों को लागू करके। (1) एस. 9 ऋण के नवीनीकरण के लिए अधिनियम के प्रारंभ के बाद एक विसंगति होगी कि कुछ पुराने ऋणों के नवीनीकरण के संबंध में संपूर्ण देयत 1 अक्टूबर, 1932 के बाद ब्याज समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरों के संबंध में दायित्व इस हद तक मौजूद होगा कि 5 % प्रति वर्ष। सरल ब्याज। हमारे निर्णय में कोई विसंगति नहीं है। परिणाम क्योंकि अक्टूबर तक ब्याज का पूर्ण निर्वहन 1. 1937 केवल पहले किए गए ऋणों के संबंध में प्रदान किया जाता है अक्टूबर, 1932 से पहले और यह स्थिति क्या होगी ऐसे ऋणों के नवीनीकरण की तारीख कभी भी न हो। यह होगा उपखंडों के लिए परंतुक की स्पष्ट शर्तों का परिणाम। (1) से एस. 9 जो एस के प्रावधान करता है। 8 ऋणों पर लागू 1 अक्टूबर, 1932 से पहले खींचा गया लेकिन 1 अक्टूबर के बाद नवीनीकृत किया गया, 1932 लेकिन उस तारीख के बाद किए गए ऋणों के लिए नहीं। श्री भीमासांकरम का अंतिम तर्क है कि भविष्य के ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं है जो उप-धाराओं के अनुरूप है।

[1965] 1 एस. सी. आर -

: सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट 204

(1) एस. 13 अधिनियम का और, इसलिए, जहाँ तक ब्याज ए अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, एस। 13 अकेले ही सहारा लेना होगा।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अध्याय IV ऋणों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित करता है और जहां तक 1 अक्टूबर, 1932 से पहले किए गए ऋणों का संबंध है, पुराने ऋणों के नवीनीकरण में लेनदेन को एस के दायरे में लाया गया है। 8 इसमें स्पष्टीकरण III को जोड़कर और लेन-देन एस के दायरे में 1 अक्टूबर, 1932 से उपखंडित करके। 9 उप-ओं के परंतुक द्वारा। (1) . इन प्रावधानों को बनाने के बाद, विधायिका के पास और कुछ नहीं था। जहाँ तक की जरूरत है

अधिनियम के लागू होने से पहले अनुबंधित ऋणों के नवीनीकरण में लेनदेन का संबंध था। जहां तक भविष्य के ब्याज का संबंध है, जहां तक अधिनियम के प्रारंभ से पहले के लेन-देन का संबंध है, विधायिका ने धाराओं में एक प्रावधान किया है। 12 और जहाँ तक अधिनियम के प्रारंभ के बाद के लेन-देन का संबंध है, उसने ष् में एक प्रावधान किया है। 13. वास्तव में, एस को अधिनियमित करने में विधायिका का उद्देश्य। 13 अधिनियम के प्रारंभ के बाद उपगत ऋणों पर देय ब्याज की अधिकतम दर के लिए प्रावधान करने के अलावा कोई अन्य प्रतीत नहीं होता है और क्योंकि यह निम्नलिखित है। 12 ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार विधायिका ने ऋणों को दो श्रेणियों में विभाजित किया, उसी प्रकार उसने अधिनियम के प्रारंभ के बाद देय ब्याज दरों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया। धारा 12 में इसने एस. एस. के तहत ऋणों पर देय ब्याज की अधिकतम दर निर्धारित की है। 8 और 9 और एस में। 13 उन

ऋणों के संबंध में एक विशिष्ट अधिकतम दर का प्रावधान किया गया है जिन्हें एस. एस. के तहत कम नहीं किया जा सकता है। 8 और 9 राज्य सरकार की समय-समय पर इसे बदलने की शक्ति के अधीन। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य उद्देश्य नहीं है जैसे कि एस को लागू करते समय ऋणों की एक अलग या स्वतंत्र श्रेणी का निर्माण करना। 13. एक सादे निर्माण पर

इन प्रावधानों में से, इसलिए, हम उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय एफ को बरकरार रखने में कोई कठिनाई नहीं देखते हैं। अब उन निर्णयों पर आते हैं जिनका उल्लेख किया गया था बार, समय की दृष्टि से सबसे पहला तिरुवेंगदथ अय्यंगार बनाम है। सन्नप्पन सर्वई (1)। संयोग से यह एकमात्र निर्णय है जो अपीलार्थियों के तर्क का पूरी तरह से समर्थन करता है। उस मामले में ऋण 2 अक्टूबर, 1938 के एक वचन पत्र पर देय था, जिसमें 1 अक्टूबर, 1931 के पूर्व वचन पत्र का भुगतान किया गया था। जिला मुन्सिफ ने उप-क्षेत्रों पर परंतुक लागू किया था। (1) एस. 9 और ऋण को पहले के ऋण के नवीनीकरण के रूप में माना, जिस पर 22 मार्च, 1938 तक ब्याज देना था। 5 प्रतिशत तक बढ़ा। उच्च न्यायालय ने कहा कि उस धारा के तहत तंत्र को कम करने का प्रभाव केवल अधिनियम के प्रारंभ की तारीख तक ब्याज में कमी करने का है और

(1) आई. एल. आर. (1942) पागल। 57 .आई।

कहा कि इससे उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि विधान इस धारा का उन ऋणों पर लागू होने का इरादा नहीं था जिनके पास था समय के अंतिम बिंदु से पहले कोई अस्तित्व नहीं है जिस तक स्केलिंग अधिनियम के तहत प्रभाव डाला जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा था एस के प्रावधानों की दृष्टि नहीं खोई। 12 जो सशक्त करता है शुरू होने के बाद भविष्य का ब्याज देने के लिए अदालत अधिनियम लेकिन यह इंगित किया कि वह धारा एक पर लागू नहीं होगी ऋण जो 22 मार्च, 1938 के बाद पहली बार लिया गया था। और इसलिए एस। 9 पहले के ऋण पर लागू नहीं होगा 22 मार्च, 1938 के बाद नवीनीकरण किया गया। उच्च न्यायालय ने तब टिप्पणी की:" यह हमें लगता है कि, की योजना को ध्यान में रखते हुए स्केलिंग में नवीनीकरण के सिद्धांत को पेश करने के लिए बाद में किए गए ऋणों के संबंध में डाउन ऑपरेशंस अधिनियम की शुरुआत, कुछ विशिष्ट प्रो इस संबंध में दृष्टिकोण बनाए गए होंगे। हम. उनकी राय है कि इसके बाद किए गए सभी ऋणअधिनियम का आम आदमी, चाहे वे इस में हों पूर्व ऋणों का प्रभार या नहीं, केवल इसके अंतर्गत आएगा धारा 13 "। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का उत्तर यह होगा कि सबसे पहले कानून के प्रत्येक प्रावधान को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इस कानून को लागू करने में विधायिका का उद्देश्य जो प्रदान

करना था किसानों को राहत और इसका कोई भी लाभकारी उपायजहाँ तक अनुमति है, प्रकार की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो विधानमंडल के विचार में था। हम अपने निर्णय में जो पहले कह चुके हैं, वह इसके अनुरूप है। इन सिद्धांतों और एस. एस. की व्याख्या करके। 9 और 13 जिस तरह से हम दोनों में से किसी की भी भाषा पर कोई हिंसा नहीं की जाएगी। इन प्रावधानों। उच्च न्यायालय के फैसले का आधार ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक कि प्रत्येक लेन-देन के बाद नहीं किया जाता है अधिनियम के प्रारंभ को इसके दायरे में लाया जा सकता है - एस. 9 , उप-एस। (1) वह प्रावधान उस पर बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता था वह तिथि हो सकती है जिस पर मूल ऋण उत्पन्न हुआ था। के साथ सम्मान, हम दोनों पेशेवरों को इस तरह से समझने का कोई कारण नहीं देखते हैं दर्शन अर्थात्, एसएस। 9 (1) और 13. हमारे निर्णय में यह पर्याप्त है कि कहते हैं कि दोनों प्रावधानों को पूरा प्रभाव देना होगा और वेइन्हें सामंजस्यपूर्ण तरीके से समझा जाना चाहिए। अगला निर्णय अरुणगिरी चेट्टियार बनाम है। कुप्पुस्वामी चेत टियर (1)। यह उन दो न्यायाधीशों में से एक का निर्णय है जो (1) [1942] 2 एम. आई. जे. 275 .पी।

14 [1965] आई एस. सी. आर. 206

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो ऋणी द्वारा अधिनियम की शुरुआत के बाद लेनदार को भुगतान किया गया था। विद्वत न्यायाधीश के दावे को नकारना देखा गया:" 1938 और 1939 में दो भुगतान निश्चित रूप से थे। ब्याज के लिए उस समय विनियोजित किया गया जब वे नाए गए थे। न तो देनदार ने और न ही लेनदार ने एक संघ द्वारा इन विनियोगों को फाड़ने का अधिकार मूलधन को भुगतान का मूल्य निर्धारित करें जब तक कि अधिनियम लागू न इस तरह के पुनर्विनियोजन के लिए एक प्रावधान है। मैं हूँ। 1938 के अधिनियम IV में ऐसे किसी भी प्रावधान की जानकारी नहीं है। तब विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि एक ऋणी को धन वापस पाने का एकमात्र तरीका जो उसने अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित रूप से देय राशि से अधिक राशि का भुगतान करने के बाद किया है, वह होगा सामान्य कानून के तहत धनवापसी का अधिकार इस आधार पर स्थापित करना कि भुगतान किया गया था एक गलती से। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि इस मामले में शामिल मामला हमारे सामने वाले मामले से अलग है। अगला निर्णय मेल्लाचेरुवु पुंडरिकक्षुडु बनाम है। कुप्पा वेंकट कृष्ण शास्त्री (1)। वह एक पेशेवर पर आधारित सूट था 18 अगस्त, 1948 का संदेश पत्र जो ई के नवीनीकरण में था 14 अगस्त, 1945 को वचन पत्र निष्पादित किया गया। इस प्रकार यह एक मामला जो एस द्वारा कवर किया गया था। 13 अकेले। विद्वान न्यायाधीशों ने एस के तहत उचित रूप से अभिनिर्धारित किया। 13 ऋणी अपने ऋण का पता नहीं लगा सकता है। मूल ऋण जो

स्वयं अधिनियम के आने के बाद वहन किया गया था वेंकट सुब्बारायुडु (1)। बाद के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था: यह है। अच्छी तरह से निपटाया गया कि पागल की शुरुआत के बाद किया गया ऋण 1938 के रास अधिनियम 4 को कम नहीं किया जा सकता है सिवाय इसके कि इसके अनुसार किया जाए। उस अधिनियम की धारा 13 के साथ। शब्द 'एक ऋण वहन' थे वास्तव में ऋण के नवीनीकरण में एक लेनदेन को शामिल करने के लिए अधिनियम के प्रारंभ से पहले खींचा गया। अतः यह जी है एक बयान जो अपीलार्थियों का समर्थन करता है लेकिन वास्तव में विद्वान न्यायाधीश 1932 से पहले के ऋण से संबंधित नहीं थे और इसलिए ऋणी को मूल ऋण के ऋण का पता लगाने में सक्षम बनाएँ आगे सवाल उठ सकता है कि क्या तथ्यों के आधार पर प्रावधान () एल. एल. आर. [1957] ए. पी. 532 (2) आई. एल. आर. 1942 पागल। 57 .(3) [1952 } 1 एम. एल. जे. 638 कृष्णय्या वी. सेशाचलम (मुधोलकर)। जे.)207 एस. 9 अधिनियम के प्रारंभ के बाद उपगत ऋण की ओर आकर्षित होते हैं (इस अर्थ में कि इससे संबंधित अंतिम लेन-देन अधिनियम के प्रारंभ के बाद हुआ था) क्योंकि मूल दायित्व अधिनियम के प्रारंभ से पहले उत्पन्न हुआ था। अगर एस. 9 परंतुक को उप-ओं की ओर आकर्षित किया जाता है। (1) यदि तथ्य इसकी अनुमति देते हैं तो कुछ ऋणों का पता लगाने की अनुमति दी जा सकती है। फिर मल्लिकार्जुन राव बनाम में निर्णय है। त्रिपुरा सुंदरी (1)। यह एकल न्यायाधीश, राजमन्नार

सी. जे. का निर्णय था, जिन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि जहां मद्रास कृषि कृषक राहत अधिनियम के आधार पर देय राशि से अधिक राशि के लिए वचन पत्र निष्पादित किया जाता है, वहां अतिरिक्त राशि पर विचार करने में विफलता होती है और वादी उस अधिनियम के प्रावधानों को मूल ऋण और उसके नवीनीकरण पर लागू करने के बाद उससे अधिक का हकदार नहीं होगा। अगला निर्णय नैनमुल बनाम पर निर्भर है। बी. सुब्बा राव (2)। पूर्ण पीठ की राय के लिए जिस बिंदु को भेजा गया था, वह इस प्रकार था: " क्या अधिनियम के बाद किए गए ऋण के मामले में अनुबंध दर पर ब्याज को फिर से खोला जा सकता है और के अधीन देय ब्याज के लिए विनियोजित एस के प्रावधान। 13 अधिनियम "। पूर्ण पीठ ने इस सवाल का जवाब हां में दिया। इस प्रकार यह निर्णय श्री भीमासांकरम की दलीलों के खिलाफ है। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसके समर्थन में सुब्बा राव सी. जे. (जैसा कि वे उस समय थे) की निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत किया जा सकता है: " तय किए गए मामलों से परेशान हुए बिना, मैं परामर्श के लिए आगे बढ़ूंगा कृषकों को ब्याज के मामले में राहत अधिनियम के बाद उपगत ऋण का संबंध। अगर ऐसा है तो ऋण को लागू करने की कोशिश की जाती है, यह जाल में फंस जाता है स्केलिंग डाउन प्रक्रिया। उस स्तर पर, ऋण पर बकाया ब्याज है वैधानिक स्तर तक घटाया गया या, इसे अलग तरीके से कहें तो, ब्याज

की अनुबंध दर जो भी हो, वह है वैधानिक दर द्वारा प्रतिस्थापित। यदि अनुदान

(2) ए. एल. आर. 1957 ए. पी. 546 एफ. बी.

(1) ए. आई. आर. 1953 मद्रास 975।

[1965] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पहले किए गए को फिर से नहीं खोला जाता है, का इरादा पूर्व अनुबंध दर के लिए कानून को विफल कर दिया जाएगा एक चरण तक वैधानिक दर पर निर्भर करता है। निस्संदेह अदालतें पूर्व से संबंधित हैं विधायिका के दबाव वाले इरादे। महत्वपूर्ण शब्द ' ब्याज दो शब्दों 'सभी' और 'देय' द्वारा योग्य है। यदि केवल बकाया ब्याज को कम किया जाता है जोरदार शब्द 'सभी' अस्पष्ट हो जाता है। अगर ऐसा होता। इरादा, शब्द 'बकाया ब्याज' होगा उद्देश्य की सेवा भी करें। शब्द 'सभी', इसलिए, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसे एक अर्थ दिया जाना चाहिए। यह इंगित करता है कि पूरा ब्याज, जो एक ऋण है कमाया जाता है, कम किया जाता है "। के. टी. निर्णय का उल्लेख मंसूर बनाम में किया गया है। शंकर यह उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का निर्णय था। जिन बिंदुओं पर विचार किया जाना था और न्यायालय को निम्नलिखित में सही ढंग से संक्षेपित किया गया है: मद्रास कृषक राहत अधिनियम (IV) की धारा 13 1938) अधिनियम के

बाद किए गए ऋणों से संबंधित है। उस धारा के तहत कोई प्रावधान नहीं है दर पर निर्धारित ब्याज का स्वतः निर्वहन उसमें निर्धारित से अधिक। ऐसी ज्यादाती ब्याज को केवल तभी अपरिवर्तनीय बनाया जाता है जब लेनदार इसे अदालत में लागू करने की मांग की। वहाँ है। न ही उच्च दरों का स्वचालित निर्वह एक कृषक ऋणी द्वारा भुगतान करने के लिए सहमत ब्याज, यह नहीं कहा जा सकता है कि, जब एक लेनदार के संबंध में अधिनियम के बाद उसकी सहमति से अनुबंधित ऋण देनदार ने मूल ऋण में अर्जित ब्याज जोड़ा अवैध या यहाँ तक कि इस संबंध में विचार की विफलता नए ऋण के लिए। इस तरह के नए ऋण का गठन होगानवीकरण की तारीख को उपगत ऋण और यदि एक मुकदमा उस ऋण पर आधारित है, सेक के प्रावधान 13 केवल उस ऋण की ओर आकर्षित किया जा सकता है और उस पूर्व ऋण के लिए नहीं जिसका वह नवीकरण था या प्रतिस्थापन। 1959) पागल। 97 .

कृष्णय्या वी. सेशाचलम (जे. मुधोलकर) 209

मुकदमा ऋण के पीछे जाने और आवेदन करने की शक्ति मूल दायित्व के लिए अधिनियम के प्रावधान केवल धारा 8 के तहत आने वाले मामलों तक ही सीमित है और अधिनियम के 9. लेकिन इसके तहत आने वाले मामलों में भी धारा 13 प्रतिवादियों के लिए खुली होगी -गुहार लगाएँ और साबित करें कि जिस ऋण पर मुकदमा किया गया है वह नहीं

कर सका किसी कार्रवाई का आधार बनाना या कि कोई विफलता थी इस संबंध में विचार करना। इस तरह का बचाव में कुछ भी के आधार पर या विशिष्ट नहीं है अधिनियम, लेकिन सामान्य कानून के तहत एक। मामलों में दस्तावेज, ब्याज सहित ऐसे नवीकरण अनुबंध दर, जिसका वैधानिक रूप से निर्वहन किया गया था धारा 8 और 9 के प्रावधानों के कारण अधिनियम, विचार की विफलता होगी जिस हद तक ब्याज का इस तरह निर्वहन किया गया था। यह सिद्धांत लागू होगा या नहीं हो सकता है। अधिनियम के बाद उपगत ऋण का मामला और पुनः उसके बाद नया। इन मामलों में होगा विचार की कोई विफलता नहीं, इसके किसी भी हिस्से के लिए नहीं धारा 13 द्वारा ब्याज का निर्वहन किया गया है, देनदार को भुगतान करने के लिए सहमत होने के लिए खुला होना ब्याज की उच्च निर्धारित दर "। यह फिर से एक ऐसा मामला था जहां मूल ऋण अधिनियम के प्रारंभ के लिए उप अनुक्रमिक था और इसलिए, हमारे पहले वाले से अलग आधार पर खड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस मामले में अपीलार्थियों की ओर से निर्भरता रखी गई है, उस मामले में न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को विद्वान न्यायाधीशों द्वारा उन मामलों तक सीमित कर दिया गया है जो एस के तहत आते हैं। 13 अकेले। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीशों ने तिरवेंगदथ अय्यंगार के मामले (1) में लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है, इसलिए हमारे लिए यह कहना आवश्यक है कि उस हद तक हम उनके

द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। यह याद रखना होगा कि जहां वादी अधिनियम के प्रारंभ के बाद निष्पादित दस्तावेज पर मुकदमा करता है, वहां न्यायालय को धाराओं के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होगा। 9 चूंकि दस्तावेज 1 अक्टूबर, 1932 के बाद निष्पादित किया गया है। यदि अभिवचनों से पता चलता है कि मूल ऋण अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू हुआ था, तो न्यायालय को पहले इस पर विचार करना होगा। एस से पहले के प्रावधानों के संदर्भ में दस्तावेज। 13 अधिनियम से। ऐसा नहीं है कि न्यायालय को इस तथ्य के अलावा हर चीज पर अपनी आंखें बंद रखनी पड़ेंगी कि जिस दस्तावेज पर मुकदमा किया गया था, वह अधिनियम के प्रारंभ के बाद निष्पादित किया गया था। वहाँ

(1) आई. एल. आर. (1942) पागल। 57 .

[1965] 1 एस. के. 210

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यदि न्यायालय यह पाता है कि मूल ऋण अधिनियम के प्रारंभ से पहले उत्पन्न हुआ था। 8 या एस। 9 लागू होगा और यह विचार करने के लिए प्रासंगिक नहीं होगा कि निष्पादन द्वारा अधिनियम के प्रारंभ के बाद नवीनीकरण के लिए पक्षकार ऋण के नवीनीकरण की तारीख से नवीनीकरण की तारीख तक अर्जित ब्याज को मूलधन के रूप में मानने पर सहमत हुए। यह विचार उन मामलों में प्रासंगिक हो सकता है जो एस.

एस. की प्रयोज्यता को पूरी तरह से बाहर करते हैं। 8 और 9. हमें पुण्यवतम्मा में निर्णय के बारे में भी बताया गया था। वी. सत्यनारायण (1); नागभूषणम बनाम। सीतारामैया (2) और चेल्लम्मल बनाम। अब्दुल गफूर साहिब (3)। इनमें से पहले और तीसरे मामले में मूल दायित्व अधिनियम के लागू होने के बाद उत्पन्न हुआ, लेकिन दूसरे मामले में यह अधिनियम के शुरू होने से पहले उत्पन्न हुआ। हम बाद के मामले में लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं कि एस के तहत ऐसे मामले में एक कृषक को राहत दी जा सकती है। 8 या एस। 9 जैसा कि मामला हो सकता है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि जहाँ भी कोई लेन-देन किया गया था अधिनियम के प्रारंभ के बाद, लेकिन मूल ऋण संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से पहले उत्पन्न हुआ, पूर्ववर्ती दृष्टिकोण यह है कि एस. एस. 8 और 9 लागू नहीं होगा। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह भी हमारा विचार है। परिणामस्वरूप हम लागत के साथ अपील को खारिज कर देते हैं। खारिज कर दी गई। कभी-कभी

(1) आई. एल. आर. [1961] 1 ए. पी. 485.

(2) आई. एल. आर. [1960] 2 ए. पी. 111.

(3) आई. एल. आर. [1961] पागल। 1061 .

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विशाल व्यास आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

Vishal Vyas